

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।  
परिवहन विभाग,  
5/9 अण्डर हिल, दिल्ली-54

सं0एफ0 19(04) / परि0 वि0 / सचिं0 शा0 / 2018 / 361

दिनांक— ८-८-१८

सेवा में,

उप— सचिव (प्रश्न),  
दिल्ली विधान सभा सचिवालय  
पुराना सचिवालय,  
दिल्ली-54

विषय : दिनांक 09.08.2018 को सदन की बैठक में लिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं0 – 220

महोदय,

आपके पत्र के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर की 100-100 प्रतियाँ संलग्न हैं।

भवदीय,

  
(विकास जैन)  
पी.सी.ओ. (सचिं0) Officer  
Transport Department  
C/o Under Min. of Railways, New Delhi-54

विभाग का नाम	—	परिवहन, दिल्ली सरकार
विभाग का पता	—	5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली-54
अतारांकित प्रश्न संख्या	—	220
प्रश्नकर्ता का नाम	—	श्री जगदीश प्रधान
दिनांक	—	09-08-2018

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि ओला और उबर जैसी प्राइवेट टैक्सी सर्विसिस के लिए दिल्ली सरकार की कोई नीति निर्धारित नहीं है;	जी नहीं, City Taxi Scheme 2015 के अनुसार Aggregators को भी लाइसेंस लेना जरूरी है। नीति निर्धारित है।
ख)	अब तक कोई नीति निर्धारित न करने के क्या कारण हैं;	अन्य राज्यों की टैक्सियाँ ओला, उबर इत्यादि, एग्रीगेटर्स के माध्यम से चल रही हैं जिनको रेगुलेट करने के लिए City Taxi Scheme 2015 के स्थान पर नए Licensing and Regulations of App based aggregators rules बनाए गए हैं। उसको अन्तिम रूप देने के लिए मुख्यमन्त्री के आदेश से High Powered Committee का गठन किया गया है, उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद नियम लागू किए जाएंगे।
ग)	क्या सरकार इनके लिए कोई नीति निर्धारित करने पर विचार कर रही है ; और	
घ)	यदि हां, तो ये नीति कब तक तैयार हो जाएंगी?	

हस्ताक्षर

(वर्षनी जोशी)

VARSHINI JOSHI IAS  
Secretary cum Commissioner (Tpt)  
Transport Department  
GNCT Delhi  
5/9, Under Hill Road, Delhi